DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I would like to know from the hon. Minister whether he could give some kind of a time-frame, because this has been pending for many, many years, and indicate whether the matter will be decided within a particular time-frame.

SHRI R. VENKATARAMAN: I have been here for 2 weeks, and their Government was there for 2½ years. I will try to expedite it. It is a public matter and I will try to expedite it.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I would like to know from the Minister whether he is aware that in fact in the entire Bombay suburban area at least, which I represent in this Parliament, there are vast tracts of the Salt Commissioner's land. No salt is being manufactured on this land. Therefore, will he consider a general policy question of what to do with the salt land, particularly when there is acute housing shortage in this area?

SHRI R. VENKATARAMAN: This is a policy matter which cannot be answered in the Question time. Nevertheless, I will indicate that wherever lands which are not required for production of salt are brought to the notice of the Government, Government will consider the question of how to dereserve salt lands.

SHRI A. T. PATIL: I would like to know what principles or norms are being applied in taking a decision on this matter, and whether they will be of general application. The reason is that the demands of land belonging to Salt Commisioner are being made from place to place for the construction of roads and for housing and those demands have not been considered so far and no decision has been taken thereon. Therefore, I would like to know what principles or norms are being applied in taking a decision on this matter and whether they will be of general application.

SHRI R. VENKATARAMAN: The consideration is public interest. If the needs of the public are greater, then the salt land is dereserved and then roads are allowed to be put up. As I said, it is only public interest that will be the paramount consideration.

Border Clashes with Bangladesh

*42. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the HOME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there have been border clashes between our forces and forces of Bangladesh this month; and

(b) if so, the reasons therefor?

गृह मंत्री (श्री ज़ैल सिंह) : (क) तथा (ख): जी नहीं, श्रीमान । किन्तु दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया उप मंडल में मुहुरी चारलैंड में भारतीय राष्ट्रिकों को अपनी फसलों को काटने से रोकने के लिए बंगला देश राइफल्स कार्मिकों ने अकारण गोली चलाई । भारतीय राष्ट्रीकों की सुरक्षा के लिये सी० सु० बल ने जवाब में गोली चलाई ।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I want to know whether nationals are being protected and they have reaped the crops. Whether they have received injuries. What protection has been given to them to reap the crops afterwards?

श्री ज़ैल सिंह : स्पीकर साहब, जहां तक नेशन को प्रोटेक्ट करने का सवाल है, उसके लिए हमारे बी० एस० एफ० के जवान और हमारे फौजी भाई वहां पर तैनात हैं। और मैं यह चाहता हूं, चूंकि 8 जनवरी के बाद वहां कोई वाक्या नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रश्न पर ज्यादा सप्लीमेंट्रीज न हों । यह बार्डर का मसला है और इस से हम एमीकेबली सेटिल करने को तैयार हैं, और उसमें कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए ।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Whether it figured in the discussion between our Prime Minister and the President of the Bangladesh when he came here recently.

श्री ज़ैल सिंह : पी० एम० और प्रेजीडेंट की जो बातचीत हुई है, उस के मामले में न तो मुझे बताना चाहिए और न ही, मैं कहना हूं कि मुझे मालूम है । इस लिए कि पी० एम० और प्रजीडेंट बंगला देश के दरम्यान जो बातचीत हुई उसम मैं शामिल नहीं था । (व्यवधान)

आनरेबल मेम्बर साहिबान इस पर बात बेचैन न हों। मैं समझता हूं कि दो देशों के हैड्ज के दरम्यान और कोई मुलाकात होती है और उसमें अगर कोई भी अफसर शामिल नहीं होता है और मिनिस्टर भी शामिल नहीं होता है तो यह प्राइम मिनिस्टर का प्रिवलेज है कि वह बताएं कि क्या बात हुई और क्या नहीं हुई।

SHRI INDRAJIT GUPTA: I will not press the Minister to reveal anything about the talks because he pleads ignorance. But when this firing across Tripura border was taking place day after day, it was being alleged by Bangla Desh authorities, according to the Press, that certain land, the charland which is in the middle of the river on which the Indian farmers were cultivatinug, they were cultivating that land for quite a long time, that that land did not belong to India and that it rightfully belonged to Bangla Desh. I am not asking him what transpired between the Prime Minister of India and the President of Bangla Desh, Zia Ur Rahiman, because he says he will not be able to reply; it is a pathetic spectacle. Anyway, at least I should like to know what is the view of the Government of India, whatever settlement may be reached later on. I hope some peaceful settlement will be reached. But at present what is the view of the Government of India regarding that so-called disputed—not disputed from our side perhaps, disputed from the Bangla Desh side—territory or land which led to this exchange of fire.

श्री बेल सिंह : यह सवाल दुरुस्त है और इसका जवाब मैं देता हूं। महोली रिवर जिसको प्रिंसली स्टेट के वक्त भी एक हद माना गया था उसने अपना रास्ता बदल लिया और रास्ता बदलने से कुछ एकड़ जमीन जो पहले बंगला देश में थी वह दरिया द्वारा रास्ता बदलने से भारत में आ गई और कुछ ऐसी जगह भी है जो रास्ता बदलने की वजह से भारत की जमीन दूसरी तरफ चली गई है। बंगला देश वाले यह क्लेम करते हैं कि चूंकि दरिया के बदलने से इलाका नहीं बदल जाता इस वास्ते हमको यह जमीन मिलनी चाहिए और यह हमारी है। इस मामले पर अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। बातचीत हुई थी और अभी दुबारा बातचीत होने वाली है कि उस इलाके के बारे में कैसे किया जाए। लेकिन यह मानी हुई बात है कि दरिया के दर्म्यान का इलाका जो था, दर्म्यान जो हद थी उसी को हद माना गया था और उसी को हद मान कर चलते रहे हैं।

परमाणु तथा सौर ऊर्जा का विकास

43. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा का संकट है; और

(ख) यदि हां, तो परमाणु ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION AND LABOUR (SHRI J. B. PATNAIK): May I answer this, on behalf of the Prime Minister?

MR. SPEAKER: Yes.

श्री जं० बी० पटनायक : (क) देश में बिजली की कमी है, चाहे वह परमाणु ऊर्जा से मिलने वाली बिजली हो, चाहे जीवाश्म ईंधनों से या पानी से।

(ख) सरकार की नीति बिजली पैदा करने के सभी साधनों का विकास करने की है, जिनमें परमाणु बिजली भी शामिल है। चाल परमाणु बिजलीघर 640 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इसके अलावा, यह आशा है कि निर्माणाधीन बिजलीघर इस दशाब्द के मध्य तक 1160 मेगावाट बिजली पैदा करने लगेंगे। परमाणु बिजली के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए, जिसमें इसे बिजली में सीधे ही बदलना भी शामिल है, प्रौद्योगिकी का विकास करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जाए।

श्री राम विलास पासवान : मैं जानना चाहता हूं कि अमरीका से यूरेनियम की आपूर्ति की स्थिति अभी क्या है क्योंकि आपके सभी बिजलीघर उसी पर चलते हैं?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तारापुर के लिए कोई वैकल्पिक ईंधन तैयार करने की योजना पर विचार कर रही है या पहले किया गया है?

SHRI J. B. PATNAIK: The present position is, the enriched uranium that we are expecting from the United